

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) अभियुक्तों व वारंटियों की गिरफ्तारी



सोनभद्र। ब्लॉक - कोन, जिला है कि तत्काल प्रभाव से डॉक्टर और

मजबूत है। आम आदमी को इस ज़रूरी चाकित्ता सुविधाएँ उपलब्ध होना चाहिए। और पीडा को देखते हुए हताशा मंच, अपना दल एस के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद पटेल दायलु ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और अपना अध्यक्ष दल एस के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से मांग की गई कि क्लक - कोन के सरकारी अस्पताल में कम से कम 5 डॉक्टर तैनात किए जाएं, जिसमें एक महिला डॉक्टर की उपस्थिति अनिवार्य हो। क्षेत्र की गरीबी और लगातार हो रही असमय मौतों को देखते हुए यह आवश्यक हो गया

भारतीय जनता पार्टी व मोदी जी के है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को



(आधुनिक समाचार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु)



र की कमी,कैबिनेट
गे लिखा पत्र
माननीय आशीष पटेल ने इस

आनंद पटेल दयालु ने कहा कि आशीष ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे केवल नेता नहीं बल्कि आम जनता की आवाज हैं। उन्होंने पहले भी तेलगुडूवा से कोन सड़क के टेंडर को जिला अधिकारी तक आदेश दिलवाकर बनवाने का कार्य किया और अब डॉक्टर एवं दवा की सुविधा के लिए सीधा स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भेजवाकर क्षेत्र की जनता को एक बार फिर उम्मीद दी है। ब्याक-कोन की जनता आजीवन आभार रहेगी ऐसे जननायक के लिए, और उनकी जय-जयकार करती रहेगी।

(आधुनिक समाचार चोपन पुलिस द्वारा शान्ति



(आधुनिक समाचार नेटवर्क) स्कूलों/कॉलेजों, धार्मिक स्थलों तथा



सोनभद्र। कुसाही बढौली के लिए जनता मे हाहाकार मचा हुआ



त भग के दृष्टिगत
युक्तगण गिरफ्तार
चोपन पुलिस द्वारा शान्ति

में बुधवार को सदर ब्लॉक के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बीएमएम वे

(आधुनिक समाचार नेटवर्क)



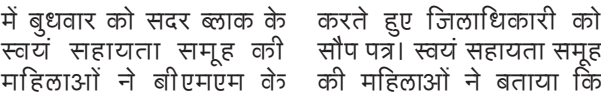
सोनभद्र। कलेक्ट्रेट परिसर रखते हुए जिलाधिकारी नामित



सोनभद्र। समाजवादी पार्टी यदि किसी पार्टी में सम्मान है तो



सोनभद्र। कलेक्ट्रेट परिसर ट्वांसफर पर विरोध प्रदर्शन गलत तरीके से पत्राचार किया



(आधुनिक समाचार नेटवर्क)



सोनभद्र। बहुजन समाज पार्टी के नेतात्वार्थान में जिला स्तरीय कार्यकर्ता समीक्षा बैठक रमेश कुशवाहा के अध्यक्षता में राबर्टसगंज नगर पालिका अंतर्गत स्वामी विवेकानंद प्रेक्षागृह सोनभद्र में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि के रूप में विनोद बागड़ी मुख्य सेक्टर प्रभारी मिर्जापुर मंडल /वाराणसी मंडल रहे। विशिष्ट अतिथि अमरगंजीत गौतम मुख्य सेक्टर

संगठन को करें मजबूत:विनोद बागड़ी
कारवां को पूरा करने को संगठन संकल्पित

प्रभारी मिर्जापुर मंडल जगन्नाथ पाल मुख्य सेक्टर प्रभारी मिर्जापुर मंडल गुरू राम मुख्य सेक्टर प्रभारी मिर्जापुर मंडल पनालाल मुख् मंडल प्रभारी मिर्जापुर मंडल लल्लू गौतम मुख्य सेक्टर प्रभारी मिर्जापुर मंडल प्रीतम गिरी रामविचार गौतम जिला प्रभारी भी सागर साहब जिला संयोजक अरविदेव निषाद जिला संयोजक हीरालाल सायन साहब पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अविनाश शुक्ला पूर्व मुख्य मंडल प्रभारी मिर्जापुर मंडल रहे। बैठक का संचालन डा। राम अवतार चौहान पूर्व जिला महासचिव ने किया। बैठक में संकोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले एक मिशन है मिशन मूवमेंट आगे बढ़ाने के लिए समय-समय से अपने संतो गुप्तों महापुरुषों से उनमें जीवन को सुरक्षा कर दिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपने जीवन काल में शोषित वंचित समाज के लिए संघर्ष करते रहे बाबा साहब के अधूरे कारवां को पूरा करने के लिए बहुजन नायक मान्यवर मसीहा कौशरीया साहब ने बहुजन समाज पार्टी का स्थापना कर आयुक्त लेडी बहान कुमार मायावती के नेतृत्व में बसपा की सरकार बनाने का काम किया और कारवां चलता रहा आगे बढ़ता रहा इस कारवां को रुकने नहीं देना है लेकिन राजनीतिक मास्टर चाली जब तक बहुजनों के हाथ में नहीं आणीत तब तक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तर्ज पर चलने वाली बहुजन समाज का मूवमेंट आगे नहीं बढ़ पाए इसलिए सर्व समाज के हित के लिए बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने की जरूरत है तभी सर्व समाज के लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा हो सकती है।

अमेरिका-चीन के बीच ट्रेड टॉक- फ्रेमवर्क पर सहमति बनी, यूएस को रेयर अर्थ मिनरल मिलने की उम्मीद,ट्रम्प-जिनपिंग की मंजूरी के बाद डील होगी

नयी दिल्ली। अमेरिका और चीन के अधिकारियों के बीच लंदन में 9-10 जून को हुई बातचीत के बाद ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनी है। यह वार्ता दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद को सुलझाने के लिए हुई। अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने मंगलवार को कहा कि इस सहमति से रेयर अर्थ मिनरल्स और मैंगनेट्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि यह फ्रेमवर्क पिछले महीने जेनेवा में हुए समझौते को मजबूती देता है। लुटनिक ने बताया इस समझौते में कुछ अमेरिकी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन को हटाने की भी बात हुई। ये फ्रेमवर्क अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। इस डील से अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स मिल सकते हैं, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों और सेप्टी इक्व्यूपमेंट के लिए होता हैं।

यह फ्रेमवर्क अभी अंतिम नहीं है।

था। जिनेवा में दोनों देशों के बीच



इसे लागू करने से पहले दोनों देश अपने नेताओं की मंजूरी लेंगे। अमेरिका इसे राष्ट्रपति ट्रम्प के सामने रखेगा, और चीन इसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने प्रस्तुत करेगा। अगर किसी एक ने भी इसे खारिज किया, तो ये प्रक्रिया फिर रुक सकती है। अमेरिका और चीन के बीच लम्बे समय से जारी ट्रेड वॉर ने वैश्विक स्फ़ाई चेंन को प्रभावित किया था। यह समझौता इसे सुधार सकता है।इससे पहले अमेरिका और चीन के बीच 11 मई को जेनेवा में ट्रेड डील पर सहमति बनी थी। दोनों देशों ने टैरिफ में 115फीसदी कटौती का ऐलान किया

हूए समझौते के मुताबिक अमेरिका, चीनी सामानों पर 30फीसदी टैरिफ लगाएगा। वहीं चीन, अमेरिकी सामानों पर 10फीसदी टैरिफ लगाएगा। दोनों देशों के बीच टैरिफ में यह कटौती फिलहाल 90 दिनों के लिए हुई।क्वाइट हाउस ने 11 मई को एक बयान में चीन से व्यापार समझौते की घोषणा की थी। हालांकि क्वाइट हाउस ने तब इसकी डिटेल नहीं दी थी। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे व्यापार घाटा कम करने के लिए एक डील बताया था, जबकि चीनी अधिकारियों ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अहम सहमति बनी है और नए सिरे से

आर्थिक बातचीत शुरू करने पर सहमति हुई है। पिछले महीने ट्रम्प ने चीनी सामानों पर 145फीसदी टैरिफ लगा दिए थे, जिसके बदले चीन ने भी अमेरिकी सामान पर 125फीसदी तक का टैरिफ लगा दिया था। जिससे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सालाना 600 अरब डॉलर का व्यापार लगभग रुक गया था। रेयर अर्थ एलिमेंट कुल 17 होते हैं, जिनमें लैथैम, नियोडियम, प्रासियोडियम जैसे मिनरल्स शामिल हैं। ये दिखने में आम खनिज जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें विशेष मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक गुण होते हैं जो उन्हें तकनीकी उत्पादों के लिए जरूरी बनाते हैं। ये 'रेयर' (दुर्लभ) कहलाते हैं, ये धरती के अंदर पाए जाते हैं। साथ ही इन्हें निकालने और इनका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस काफी जटिल और महंगा होता है।रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल कई आधुनिक तकनीकों और इंडस्ट्री में होता है। जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स (स्मार्टफोन, लैपटॉप, और टीवी), इलेक्ट्रिक वाहन, विड ट्रब्रान, सौर पैनल और बैटरी शामिल हैं।चीन रेयर अर्थ मिनरल्स का दुनिया क सबसे बड़ा उत्पादक है। यह वैश्विक आपूर्ति का लगभग 60-70फीसदी हिस्सा कंट्रोल करता है। 2023 तक, चीन ने अपनी खनन और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में भारी निवेश किया।

बांग्लादेश में टैगोर के पैतृक आवास पर कट्टरपंथियों का हमला ,उपद्रवियों ने तोड़-फोड़ की; पुलिस ने कार्रवाई नहीं की

ढाका। बांग्लादेश के

हैं। गुरुदेव रबिन्द्रनाथ टैगोर के

कचहरी घर में तोड़फोड़ करने

सिराजगंज में मंगलवार को कट्टरपंथियों की भीड़ ने गुरुदेव रबिन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास पर हमला कर दिया। कचहरी घर के नाम से मशहूर टैगोर के पैतृक आवास में जमकर तोड़फोड़ की। जमात-ए-इस्लामी और हिफाजत-ए-इस्लाम के कट्टरपंथियों की भीड़ ने टैगोर के विरोध में नारे भी लगाए। सूचना मिलने के बाद



शहजादपुर थाने की

पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन

आरोपियों के खिलाफ कोई

कार्रवाई नहीं की गई। थाना

प्रभारी असलम अली का कहना

है कि फिलहाल मामले की

पड़ताल की जा रही। अभी

एफआईआर दर्ज नहीं की गई

है। काफी देर तक चले हंगामे

के बाद पुलिस लौट गई, लेकिन

शाम तक कट्टरपंथी मौके पर

जमा रहे। बात दें कि राजधानी

ढाका से लगभग 125 किमी की

दूरी पर स्थित गुरुदेव टैगोर के

इस दो मंजिला पैतृक आवास को म्यूजियम का दर्जा दिया गया

है। गुरुदेव रबिन्द्रनाथ टैगोर के

कचहरी घर का निर्माण 1840

में कराया था। कट्टरपंथियों ने

आरोप लगाया कि मंगलवार को

म्यूजियम के निदेशाल किराजुल

इस्लाम ने एक व्यक्ति को बंधक

बनाकर मारपीट की। जबकि

इस्लाम ने ऐसी किसी भी घटना

से इनकार किया है। पुलिस जांच

में भी किसी को भी म्यूजियम

में बंधक बनाए जाने की बात

सामने नहीं आई। लेकिन देखते

ही देखते कट्टरपंथियों की भीड़

मौके पर जमा हो गई। बताया

पाकिस्तान से लादेन के कनेक्शन की सामने आई सच्चाई! जयशंकर ने दुनिया के सामने फिर खोली ‘आतंकिस्तान’ की पोल

नयी दिल्ली। विदेश मंत्री

एस. जयशंकर ने बेल्जियम

सीमा पर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर एक बार फिर सवाल उठाया है। विदेश मंत्री ने आतंकी ओसामा बिन लादेन का उदाहरण देकर पाकिस्तान को दुनिया के सामने फिर से नंगा किया है। इसके साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सीमा पर आतंकवाद का मुकाबला करने और देश की प्रगति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर भी अपनी बात रखी।जयशंकर ने

पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की कार्रवाई को दो परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों के बीच प्रतिशोध के रूप में पेश करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मीडिया की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं - ओसामा बिन लादेन नाम का एक आदमी था। वह सभी लोगों में से, वेस्ट प्वाइंट

के ठीक बगल में एक पाकिस्तानी सैन्य शहर में वर्षों तक सुरक्षित

बात इस चुनौती को भारत से अलग करती है, वह यह है कि



क्यों महसूस करता था मैं चाहता हूँ कि दुनिया समझे - यह केवल भारत-पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है। यह आतंकवाद के बारे में है। और यही आतंकवाद अंततः आपको परेशान करेगा।एस जयशंकर, पाकिस्तान प्रायोजित सीमापार आतंकवाद पर- ‘आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं है। यह सभी के लिए एक चुनौती है। लेकिन जो

अक्सर विभिन्न देशों में, एक समूह या ताकतों का समूह इसे अंजाम देता है। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई देश इसे खुले तौर पर राज्य की नीति के रूप में इस्तेमाल करे। यूरोप में आतंकवाद होता है, लेकिन कोई भी पड़ोसी यूरोपीय देश आतंकवाद को घोषित राज्य नीति के रूप में नहीं अपनाता है।' जब उनसे पूछा गया कि यूक्रेन पर

काहना यह है' विं हम निर्दंशात्मक या निर्णायक नहीं हैं - लेकिन हम असंबद्ध भी नहीं हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के यूक्रेन और रूस दोनों के साथ मजबूत संबंध हैं, लेकिन याद दिलाया कि जब पाकिस्तान ने आजादी के बाद भारत पर हमला किया था, तो पश्चिमी देश इस्लामाबाद के साथ खड़ा था।

यूएन की कमिटी में पाकिस्तान की बढ़ी भूमिका... क्या भारत के लिए है चिंता की बात

नयी दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को अहम भूमिका

कोई भी गैर-स्थायी सदस्य किसी न किसी समिति का अध्यक्ष जरूर बनता

किसी व्यक्ति को सूची में शामिल या बाहर नहीं कर सकता है, क्योंकि



मिली है। पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद की दो महत्वपूर्ण समितियों में 2025-26 के लिए गैर-स्थायी सदस्य के रूप में जगह बनाई है। यह 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और 1373 आतंकवाद निरोधक समिति का उपाध्यक्ष भी है। पाकिस्तान को यह पद ऑपरेशन सिंदूर के लगभग एक महीने बाद मिला है। ऐसे में यह सवाल है कि पाकिस्तान की नई भूमिका क्या भारत के लिए चिंता की बात है। तो इसका जवाब है कि भारत को इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की भूमिका संयुक्त राष्ट्र में भारत के हितों के लिए सीधा खतरा नहीं है। पाकिस्तान को इन समितियों में पद मिलना एक प्रक्रिया का हिस्सा था। यूएन चार्टर के अनुच्छेद 28 के अनुसार, ये सभी समितियां यूएनएससी के 'सहायक अंग' मानी जाती हैं। इसका मतलब है कि 1988 टीएससी और 1373 टीएससी दोनों में यूएनएससी के सभी 15 सदस्य शामिल होते हैं। दो साल के लिए यूएनएससी का सदस्य बनने के बाद,

है।ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूएनएससी के स्थायी सदस्य (चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस) प्रतिबंध समितियों की अध्यक्षता नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है ताकि हितों का टकराव न हो, क्योंकि वे प्रतिबंधों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाकिस्तान को यूएनएससी का गैर-स्थायी सदस्य चुने जाने के बाद ही यह तय हो गया था कि उसे किसी समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा।हालांकि, इस बात के भी सबूत हैं कि किसी देश की क्षमता, इच्छा और राजनीतिक स्थिति को देखकर ही यूएनएससी का अध्यक्ष किसी सदस्य को किसी समिति का अध्यक्ष बनाता है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को 1988 समिति का अध्यक्ष बनाने के लिए यूएनएससी को उस पर भरोसा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पास समिति की बैठकों का एजेंडा तय करने का अधिकार होगा। अध्यक्ष के रूप में पाकिस्तान का काम प्रतिबंधों की जांच करना और सूची में बदलाव पारित नहीं हो सका।पाकिस्तान का

इसके लिए सभी सदस्यों की सहमति जरूरी है।यूएनएससी की प्रेसीडेंसी से पाकिस्तान को कोई खास अधिकार नहीं मिलते हैं, लेकिन उसे कुछ प्रक्रियात्मक फायदे जरूर मिलते हैं। उदाहरण के लिए, प्रेसीडेंसी पाकिस्तान को यूएनएससी की बंद कमरे में/अनौपचारिक परामर्श आयोजित करने की क्षमता को बढ़ा सकती है, क्योंकि यूएनएससी के अध्यक्ष के पास ही परिषद की प्रक्रिया के अंतिम नियमों में बैठकों बुलाने का अधिकार होता है।यूएनएससी की सहायक समितियों में पाकिस्तान का प्रभाव ज्यादातर अप्रत्यक्ष रहा है। वह चीन के समर्थन से भारत द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को नामित करने के प्रयासों को रोकता रहा है। ऐसा 2022 में भी हुआ था, जब भारत ने 1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति में अब्दुल रऊफ अजहर (जो उस समय वर के उप प्रमुख थे) पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन चीन के विरोध के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका।पाकिस्तान का

न 20 डिग्री से कम, न 28 डिग्री से ज्यादा...सरकार के पास होगा आपकी एसी का रिमोट, नए नियम जान लीजिए

नई दिल्ली। भारत में अब एयर कंडीशनर के तापमान को लेकर नए नियम आने वाले हैं। सरकार एसी के तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस से कम और 28 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रखने पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह जानकारी दी है। यह नियम घरों और दफ्तरों दोनों जगह इस्तेमाल होने वाले एसी पर लागू होगा। कई देशों में पहले से ही ऐसे नियम लागू हैं। अब भारत भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। नए नियम क्या हैं, इसके पीछे मंशा क्या है, इसका क्या फायदा होगा? आइए, यहां इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना के बारे में बताया है। नए नियमों के मुताबिक, एसी के लिए तापमान का एक नया स्टैंडर्ड लागू हो रहा है। एसी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि एसी इसी रेंज के बीच में चलेगा। न 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे और न 28 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। यह नियम घरों, कार्यालयों, मॉलों, होटलों और वाहनों सहित सभी क्षेत्रों में एयर कंडीशनर पर लागू होगा। वर्तमान में कई एसी 16 डिग्री सेल्सियस या 18 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान पर सेट किए जा सकते हैं। कुछ 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं। नया नियम इन सीमाओं को प्रतिबंधित कर देगा। सरकार एसी निर्माताओं के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि नए एसी में ये सेटिंग्स डिफॉल्ट रूप से आएं या पुराने एसी के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किए जा सकें।इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। ये ऊर्जा संरक्षण, बिजली ग्रिड पर दबाव कम करने और स्वास्थ्य से जुड़े हैं।जब एसी को बहुत कम तापमान पर (जैसे 16-18डिग्री)

चलाया जाता है तो यह बहुत अधिक बिजली की खपत करता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) के

चाहती है।विशेषज्ञों का मानना है कि बहुत कम तापमान पर एसी चलाने से शरीर को 'टेम्परेचर शॉक' लग



अनुसार, एसी का तापमान सिर्फ 1डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से लगभग 6फीसदी बिजली की बचत होती है। अगर लोग अपने एसी को 20डिग्री सेल्सियस की बजाय 24डिग्री सेल्सियस पर सेट करते हैं तो लगभग 24फीसदी बिजली की बचत हो सकती है। इस कदम से उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कमी आएगी और राष्ट्रीय स्तर पर भी ऊर्जा की भारी बचत होगी।भारत में भीषण गर्मी के दौरान एसी का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। इससे बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाती है। एसी अकेले देश की कुल बिजली खपत का लगभग 20फीसदी (लगभग 50 गीगावाट) के लिए जिम्मेदार हैं। तापमान को मानकीकृत करने से बिजली ग्रिड पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। इससे बिजली कटौती और ब्लैकआउट से बचा जा सकेगा।अधिक बिजली खपत का मतलब है अधिक जीवाश्म ईंधन (जैसे कोयला) जलाना। इससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन बढ़ता है। इसका जलवायु परिवर्तन में योगदान होता है। ऊर्जा दक्षता में सुधार करके सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करना

सकता है जब कोई व्यक्ति ठंडे कमरे से बाहर निकलकर भीषण गर्मी में आता है। इससे सर्दी, थकान और यहां तक शरीर के आंतरिक अंगों पर भी तनाव पड़ सकता है। 22डिग्री सेल्सियस से 24डिग्री सेल्सियस का तापमान शरीर के लिए आदर्श माना जाता है। यह आराम प्रदान करता है और बाहर के तापमान के साथ बहुत बड़ा अंतर नहीं पैदा करता। 20डिग्री सेल्सियस पर 28डिग्री सेल्सियस का यह दायरा आरामदायक और स्वास्थ्यवर्धक है।यह नियम लोगों को ज्यादा जिम्मेदार और ऊर्जा-सचेत तरीके से एसी का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।भारत का एसी के तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तय करने का कदम ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है। कई देश ऊर्जा बचाने और उत्सर्जन कम करने के लिए इनडोर कूलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देशों ने इन नियमों को आधिकारिक बना दिया है, जबकि अन्य उन्हें मजबूत सिफारिशों के तौर पर मानते हैं।इटली ने स्कूलों और डाकघरों जैसी सार्वजनिक इमारतों में कूलिंग

